भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. *101

(जिसका उत्तर सोमवार 8 दिसंबर, 2025 /17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

खपत-आधारित विकास का आर्थिक प्रभाव

***101. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत बनी रही है और वर्ष 2025-26 के लिए खपत-आधारित विकास दर में और सुधार होने का अनुमान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा खपत में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित राजकोषीय अथवा नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी खपत को संतुलित करने के लिए कोई नई नीति बनाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खपत में वृद्धि के संभावित प्रभाव के संबंध में सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

खपत-आधारित विकास के आर्थिक प्रभाव के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (ति.1) में 7.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (ति.2) में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि की तीव्र गति को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के 62.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 62.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्य अवधि में यह 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई है।

(ख) सरकार ने मांग सहायक उपायों, आय में वृद्धि करने वाली आपूर्ति पक्ष की कार्यनीतियों और संरचनात्मक सुधारों के संयोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में खपत वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति शुरू की है। ₹12 लाख तक की वार्षिक आय के लिए नई आयकर छूट, हाल ही में जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने, व्यापार में सुगमता, कौशल प्रदान करना, रोजगार सृजन और अवसंरचना के विकास पर निरंतर ध्यान दिए जाने के साथ-साथ मुद्रा और पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण तक पहुंच बढ़ाने जैसे नीतिगत उपायों से अर्थव्यवस्था में खपत वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

(ग) विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से, सरकार ने ग्रामीण और शहरी खपत में संतुलित विकास हासिल करने पर जोर दिया है। शहरी केंद्रों में कर राहत और डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ-साथ शहरी आजीविका और कौशल कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में खपत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ-साथ, पीएम-किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), कृषि-उत्पादकता मिशन और स्वयं सहायता समूह-आधारित आजीविका पहल जैसे लक्षित प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आय संबंधी लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं।

(घ) खपत मांग के सुदृढ़ीकरण से घरेलू आय को सहायता प्रदान करके, निजी निवेश को प्रोत्साहित करके और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करके समग्र आर्थिक कार्यकलाप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

*****